THE CHILD MARRIAGE RESTRAINT ACT

1. ***What should be the minimum age of bride and bride-groom at the time of marriage?***

Ans. Bride-18 years, Bride-groom-21 years

2. ***What are the various offences under this Act and the punishment prescribed for such offences and whether the parties to the Child Marriage can also be punished?***

Ans. Punishment for performing child Marriage.

Where a bridegroom, who is above 18 years of age, has married with a girl who is below 18 years of age, the bridegroom can be sentenced to rigorous imprisonment up to 2 years and/or fine of upto Rs.1 lakh.

All such persons, who perform, conduct, or direct or abet any child marriage, may be sentenced to rigorous imprisonment up to 2 years and/or fine of upto Rs.1 lakh.

Where a child contracts a child marriage, any person having charge of the child, whether as parent or guardian or any other person or in any other capacity, lawful or unlawful, including any member of an organization or association of persons who does any act to promote the marriage or permits it to be solemnised, or negligently fails to prevent it from being solemnized, including attending or participating in a child marriage, shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to two years and shall also be liable to fine which may extend upto Rs.1 lakh.

Provided that no woman shall be punishable with imprisonment.

It shall be presumed, unless and until the contrary is proved, that where a minor child has contracted a marriage, the person having charge of such minor child has negligently failed to prevent the marriage from being solemnised.

Offences punishable under this Act are cognizable and non-bailable.

<u>बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम</u>

प्रश्न विवाह के समय वर और वधू की कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए ?

उतर वधू – 18 वर्ष और वर – 21 वर्ष

प्रश्न इस अधिनियम के तहत विभिन्न अपराध और उनकी विभिन्न सजाएं क्या हैं और क्या बाल विवाह कराने वाले पक्षों को भी सजा दी जा सकती है ?

- यदि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ होता है तो लड़के को 2 साल सश्रम कारावास और/या एक लाख रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

- ऐसे सभी व्यक्ति जो बाल विवाह करते हैं या करवाने में भूमिका निभाते हैं उन्हें 2 साल सश्रम कारावास और/या एक लाख रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

- यदि कोई माता-पिता, बच्चे के अभिभावक, या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी क्षमता से, वैध या अवैध रूप से या किसी भी ऐसी संस्था के सदस्य की मदद से जो बाल विवाह करवाती हो, बाल विवाह करने के दोषी हों या किसी भी बाल विवाह समारोह में भाग लेते हों, तो वे 2 वर्ष तक सश्रम कारावास के भागी होंगे और साथ में जुर्माना एक लाख रूपये तक हो सकता है।

- इस अधिनियम के तहत किये गये अपराध गैर जमानती होते हैं।

3. What steps can be taken to stop or prevent solemnization of Child Marriages and the powers of Court to issue injunction order for prohibiting a Child Marriage?

Ans.

1. A Child Marriage Prohibition Officer may file application, or any person/NGO having information about the likelihood of solemnization of child marriage, may file a complaint giving this information to the Metropolitan Magistrate/Judicial Magistrate Ist Class.

2. The said Court can pass an injunction order restraining such marriage. Whoever knowing that an injunction has been issued against him disobeys such injunction shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine which may extend to one lakh rupees or with both.

   Provided that no woman shall be punishable with imprisonment.

   Any child marriage solemnised in contravention of an injunction order issued under section 13, whether interim or final, shall be void *ab initio*.

3. The District Magistrate may take any step for restraining a child marriage.

3. The information regarding child marriage may also be given in the police station.

4. Is the Child Marriage voidable at the option of the contracting parties and what is the limitation for filing such petition?

Ans. Voidable Marriage

The child marriage is voidable. Any party to a child marriage, who was a ‘child’ at the time of such marriage, may file a petition before the District Court for annulling this marriage. Such petition has to be filed by such party before expiry of two years of his/her attaining the majority.

प्रश्न बाल विवाह रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और बाल विवाह रोकने के लिए न्यायालय को क्या अधिकार प्राप्त हैं ?

उतर क) बाल विवाह निषेध अधिकारी या कोई भी व्यक्ति या कोई गैर सरकारी संगठन जिसे बाल विवाह होने की जानकारी हो, महानगरीय मैजिस्ट्रेट/1st क्लास मैजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

ख) न्यायालय ऐसे बाल विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। जिसको यह पता हो कि उसके विरूद्ध आदेश जारी हुऐ हैं और वह उस आदेश की अवहेलना करे तो वह इसके लिए दण्ड का भागीदार होगा और इसकी सजा दो वर्ष तक हो सकती है या एक लाख रूपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बशर्ते कि किसी भी महिला को कारावास की सजा नहीं होगी।

यदि कोई बाल विवाह धारा 13 के अन्तर्गत पारित ओदश के खिलाफ हो, तो वह अमान्य होगा, चाहे वह आदेश अंतरिम या अंतिम हो।

ग) बाल विवाह रोकने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट कोई भी कदम उठा सकता है।

घ) बाल विवाह की सूचना पुलिस थाने में भी दी जा सकती है।

प्रश्न क्या बाल विवाह पक्षों की इच्छानुसार अमान्यकरणीय हैं और इसके लिए याचिका दायर करने के लिए क्या सीमा है ?

उतर **अमान्यकरणीय विवाह** – बाल विवाह अमान्यकरणीय है। कोई भी पक्ष जो कि विवाह के समय बाल उम्र में था, वह जिला न्यायालय में उस विवाह को खत्म करने के लिए याचिका दायर कर सकता है। ऐसी याचिका उस पक्ष द्वारा उसके बालिग होने के बाद दो वर्ष के अन्दर दायर करनी होती है।

5. ***Who is a Child Marriage Prohibition Officer and what are his duties?***

Ans. A Child Marriage Prohibition Officer for any particular area in the State can be appointed by the State Government. Presently the protection officers appointed under "Protection of Women from Domestic Violence Act" are performing the duties of Child Marriage Prohibition Officers in their respective districts. Following are the duties of the Child Prohibition Officer:

a) to prevent solemnization of child marriages by taking such action as he may deem fit;

b) to collect evidence for the effective prosecution of persons contravening the provisions of this Act;

c) to advise either individual cases or counsel the residents of the locality generally not to indulge in promoting, helping, aiding or allowing the solemnization of child marriages;

d) to create awareness of the evil which results from child marriages;

e) to sensitize the community on the issue of child marriages;

f) to furnish such periodical returns and statistics as the State Government may direct; and

g) to discharge such other functions and duties as may be assigned to him by the State Government.

प्रश्न बाल विवाह निषेध अधिकारी कौन होता है और उसके क्या कर्तव्य होते हैं ?

उत्तर राज्य के किसी भी विशेष क्षेत्र के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस समय, "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम" के अन्तर्गत नियुक्त संरक्षण अधिकारी अपने सम्बन्धित जिलों में बाल विवाह निषेध अधिकारी के कर्तव्यों को निभा रहे हैं। बाल विवाह निषेध अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं –

क) बाल विवाह रोकने के लिए कार्यवाही करना;

ख) इस अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए सबूत जुटाना।

ग) इलाके के निवासियों को बाल विवाह को बढ़ावा देने, मदद करने, सहायता देने या अनुमति देने के खिलाफ सलाह देना।

घ) बाल विवाह से होने वाली हानियों के बारे जागरूक करना।

ड.) बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाना।

च) राज्य सरकार द्वारा निर्देशित नियतकालिक आँकड़े जुटाना।

छ) राज्य सरकार द्वारा उसे दिए गए दूसरे अन्य कार्य व कर्तव्यों को करना।